ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 82-85

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉ0 अम्बेडकर की वैज्ञानिक दृष्टि-भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में

डॉ0 शशि बाला

असि0 प्रो0– अर्थशास्त्र विभाग, म0गां0 काशी विद्यापीठ वाराणसी (उ0प्र0), भारत

Received- 22 .10. 2021, Revised- 26 .10. 2021, Accepted - 28.10.2021 E-mail: drshashibala09@gmail.com

सारांशः ***बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थशास्त्री के रूप में डॉ0 अम्बेडकर के योगदान की ओर बहुत कम विद्वानों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। वस्तुतः राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान इतना महान एवं युगांतरकारी है कि उनके जीवन के बाकी पहलुओं तक लोगों की दृष्टि जा ही नहीं पाती। अर्थशास्त्री के रूप में डॉ0 अम्बेडकर के योगदान को केवल एक लेखांश से आंकना असंभव है। अपने एक व्याख्यान में प्रख्यात अर्थशास्त्री श्रीनिवास अंबीराजन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र से राजनीति और कानून के क्षेत्र में अंतरण को अर्थशास्त्र की भारी क्षति बताया था उनका मानना था कि यदि वे राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में नहीं आते तो दुनिया भर में दिग्गज अर्थशास्त्री के रूप में स्थान पाते।***

कुंजीभूत शब्द–भारतीय संविधान निर्माता, समाज सुधार, युगांतरकारी, प्रख्यात अर्थशास्त्री, भारतीय वाणिज्य, व्यक्तित्व।

डॉ0 अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले देश के पहले अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय उनके पास कुल 29 विषय ऐसे थे, जिनका सीधा सम्बन्ध अर्थशास्त्र से था। उनकी एम0ए0 की थीसिस का विषय प्राचीन भारतीय वाणिज्य (Ancient Indian Commerce) था, जो कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। कोलम्बिया वि0वि0 से ही उन्होंने "Evolution of Public finance in British India" विषय में पी0एच0डी0 की डिग्री प्राप्त की। कोलम्बिया वि0वि0 में प्रोफेसर एवं विद्वान अर्थशास्त्री एडविन रावर्ट सेलिगमैन ने डॉ0 अम्बेडकर की पी0एच0डी0 की थीसिस की खूब प्रशंसा की। सन् 1923 में वे लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डी0एस0सी0 की थीसिस "The Problem of the Ruppee- Its origin and its solution" में उन्होंने रूपये (मुद्रा) के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया, जो कि उस समय के शोधों में सबसे व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण शोध था। उस ग्रंथ की भूमिका महान अर्थशास्त्री एडविन केनन ने लिखी थी। (m.wikipedia)

डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा (रूपये) की समस्या, मंहगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रान्तीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के तार्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिये ।

20वीं सदी के प्रारम्भ में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने डॉ0 अम्बेडकर के अर्थशास्त्र विषय की समझ तथा उनके योगदान को सराहा और उनके शोध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। वर्ष 2007 में दिये गये एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अम्बेडकर की गुरूता को स्वीकारते हुए वर्तमान समय के महान अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन ने कहा था–

"डा0 अम्बेडकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मेरे जनक हैं, वे दलितों– शोषितों के सच्चे और जाने–माने महानायक हैं। उन्हें आज तक जो भी मान–सम्मान मिला है वे उससे कहीं ज्यादा के अधिकारी हैं। भारत में वे अत्यधिक विवादित हैं, हालांकि उनके जीवन और व्यक्तित्व में विवाद योग्य कुछ भी नहीं है, जो उनकी आलोचना में कहा जाता है, वह वास्तविकता से एकदम परे है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार है उसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जायेगा।" (wordpress.com)

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉ0 अम्बेडकर के योगदान तथा इस विषय में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाने वाली घटनाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख निम्न बिन्दुओं द्वारा किया जा सकता है –

भारत की मुद्रा विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा अवमूल्यन में डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक विचार – भारत में 1893 तक केवल चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। चांदी के सिक्के का मूल्य उसमें उपलब्ध चांदी के द्रव्यमान से आंका जाता था। एक स्वर्णमुद्रा का मूल्य 15 चांदी के सिक्कों के बराबर था। 1853 में आस्ट्रेलिया और अमेरिका में स्वर्ण भण्डार मिलने से सोने की आमद बढ़ी उसके बाद स्वर्ण–मुद्राओं में विनिमय का प्रचलन बढ़ने लगा, किन्तु उसका विधिवत चलन 1873 के बाद ही संभव हो पाया। परन्तु भारत में स्वर्ण उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई थी। परिणाम स्वरूप स्वर्ण मुद्रा के मुकाबले भारतीय रजत–मुद्रा का निरंतर अवमूल्यन होने लगा। मुद्रा का अवमूल्यन होने से मंहगाई में वृद्धि हुई, जबकि आय ज्यों की त्यों बनी हुई थी, आंतरिक स्तर पर उसमें प्रत्येक वर्ग को घाटा हो रहा था। (m.wikipedia. org, rbi.org.in hindinews

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

18.com भारतीय रिजर्व बैंक संक्षिप्त इतिहास)

1899 में सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसने स्वर्ण–स्टैंडर्ड के स्थान पर स्वर्ण–मुद्रा के उपयोग की सलाह दी थी तदनुसार मुद्रा का मूल्यांकन उसमें उपलब्ध धातु – मूल्य के बजाय सरकार द्वारा अधिकृत मूल्य जितना आंका जाने लगा। सरकार ने रजत–मुद्रा का मूल्य 1 शिलिंग, 4 पेंस के बराबर कर दिया। नये नियम के अनुसार स्वर्ण–मुद्रा का मूल्य लगभग स्थिर था। उसके मूल्यांकन का अधिकार सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था जबकि रजत मुद्रा के मूल्य नियंत्रण की कोई व्यवस्था न थी। मुद्राओं के मूल्यांकन के प्रति डॉ0 अम्बेडकर का दृष्टिकोण मानवीय था। उनका मानना था कि मुद्रा का वास्तविक मूल्य उसके बदले मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं से तय होता है, सोना बेशकीमती हो सकता है लेकिन वह लोगों की सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता और न ही किसी भूखे का पेट भर सकता है। मुद्रा के प्रति जनता का अविश्वास तथा उसकी मूल्य–अस्थिरता आर्थिक संकट को जन्म देती है। इस प्रकार रजत मुद्रा के उतार–चढ़ाव के कारण अम्बेडकर ने स्वर्ण–मुद्रा अपनाने का सुझाव दिया। एक रजत–मुद्रा का मूल्य 1 शिलिंग तथा 6 पैंस रखने की सलाह दी, उनकी अधिकांश अनुशंसाओं को सरकार ने ज्यों का त्यों अपना लिया था और बाद में इसी आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की मूलभूत सैद्धान्तिक एवं नीति–निर्देशों का विकास हुआ। (Hilton yound commission Report,(Kashyap.omprakash, Gregory'R.G. (1971)). Indi and east Afrisa 1890-1939. MalinowskiB. (1929) शाही आयोग की रिपोर्ट।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त आयोग की स्थापना में डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक विचार – भारतीय उपनिवेशों में जहां आजादी की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। वहीं ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ गम्भीर चुनौतियाँ थी। 1930 का दशक भारत सहित पूरे विश्व में भीषण मंदी लेकर आया था। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्थानीय समस्याओं के मूल में कुछ वैश्विक मंदी जैसा आर्थिक संकट था और कुछ स्थानीय रोजगार के उजड़ जाने से उत्पन्न मंदी का, इसलिए अगस्त 1925 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए श्त्वलंस ब्वउउपेपवद वद प्दकपं ब्नततमदबल ंदक म्पदंदबम जिसे कि भ्पसजवद.ल्वनदह ब्वउउपेपवद के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा एक केन्द्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने सन् 1926 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) dk vkjEHk fd;kA Wordpress. com, Hilton yound commission Report, E.A. Watter-1963

इस आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिन 40 विद्वानों को आमंत्रित किया गया था, उनमें अम्बेडकर भी थे। वे जब आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तो वहाँ मौजूद प्रत्येक सदस्य के हाथों में उनकी लिखी पुस्तक 'इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' की प्रतियां थी। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1926 में प्रकाशित की थी, उसकी अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परिचालन का शुभारम्भ 01 अप्रैल 1935 से हुआ। सन् 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। (Brief bistory. R/B/I www.rbi.in Iktoday.in 2011, Report of Royal commission 1926. E. Hilton chairman)

भारतीय रिजर्व बैंक की अभिकल्पना, नियमानुदेश, कार्यशैली और रूप रेखा डॉ0 अम्बेडकर की शोध पुस्तक 'प्राब्लम ऑफ रूपया' पर आधारित है। बाबा साहब ने 1923 में वित्त आयोग के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के अन्तर पर वित्त आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए। भारत में वित्त आयोग का गठन 1951 में (भारतीय वित्त आयोग अधिनियम, 1951) किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक m.rbi.orgin, hindustanilogic (kashyap.o.p., wordpress and hindustanilogic.wordpress) रायल कमीशन ऑन इंडियन करेन्सी एंड फाइनेंस

अर्थशास्त्री के रूप में अम्बेडकर की सबसे चर्चित पुस्तक 'द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी' – एक अर्थशास्त्री के तौर पर डॉ0 अम्बेडकर की सबसे चर्चित पुस्तक 'द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन' 1923 में प्रकाशित हुई इस किताब में अम्बेडकर ने जिस धारदार तरीके से अर्थशास्त्र के बड़े पुरोधा जॉन मेयनार्ड कीन्स के विचारों की आलोचना की है। वह इकोनॉमिक पॉलिसी और मौद्रिक अर्थशास्त्र पर उनकी गहरी पैठ का प्रमाण है। कीन्स ने करेंसी के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की वकालत की थी, जबकि अम्बेडकर ने अपनी किताब में गोल्ड स्टैंडर्ड की जबरदस्त पैरवी करते हुए उसे कीमतों की स्थिरता और गरीबों के हित में बताया था। (financialxpress.com विप्लव राही, org.in Retrieved 2 जून 2021 भारतीय संस्कृति–भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग की रिपोर्ट 2 जून, 2021)

आधुनिक भारत का आर्थिक ढांचा विकसित करने में अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका – डॉ0 अम्बेडकर ने सिर्फ आर्थिक सिद्धान्तों और विश्लेषण के क्षेत्र में ही उल्लेखनीय योगदान नहीं किया, बल्कि आजादी के बाद सरकार का हिस्सा बनकर भी उन्होंने कई ऐसे काम किए, जिसमें उनकी गहरी आर्थिक सूझबूझ का लाभ देश को मिला। श्रम कानूनो से लेकर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

नदी घाटी परियोजनाओं और देश के तमाम हिस्सों तक पर्याप्त और सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास का खाका 1940 के दशक में उस वक्त तैयार किया गया था जब डॉ0 अम्बेडकर पॉलिसी कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स एण्ड इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन हुआ करते थे उनका मानना था कि देश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए यह आवश्यक है। (financialexpress.com)

डॉ0 अम्बेडकर ने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार– अम्बेडकर के दर्शन ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद की। वे मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इनका प्रस्ताव था कि कृषि राज्य का उद्योग बने अर्थात् कृषि के क्षेत्र मालिको, काश्तकारों आदि को मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करें और उस पर सामूहिक खेती कराये। इस प्रकार भीम राव ने सहकारी कृषि का समर्थन किया वे व्यापक भूमि सुधार के समर्थक थे। तथा समाज के सभी वर्गों में भूमि का समान वितरण कर सामाजिक आर्थिक स्थापना के लिए अम्बेडकर की यह क्रांतिकारी सोच थी। (hi.m.wikipedia.org.)

डॉ0 अम्बेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, बिजली, परिवहन, बैंकिग, बीमा तथा आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकसित करने पर जोर दिया उन्होंने ब्रिटिश शासन की वजह से हुए विकास के नुकसान की गणना की। (www.sansarlochan.in)

एम0एस0 स्वामीनाथन से कई दशक पहले कृषि लागत से 50 फीसदी ज्यादा डैच का डॉ0 अम्बेडकर का सुझाव – अम्बेडकर की आर्थिक दूरदृष्टि का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एम0एस0 स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश सामने आने के दशकों पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के विकास में वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ–साथ भूमि सुधार की आवश्यकता एवं महत्व पर भी उन्होंने बहुत पहले जोर दिया था। (finacialexpress.com)

कल्याणवादी अर्थशास्त्र सम्बन्धी अम्बेडकर के विचार –डॉ0 अम्बेडकर अपने अर्थशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समकक्ष नजर आते है। आगे चलकर राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, उसके आधार पर कुछ विद्वान उनके अर्थशास्त्र संबंधी सिद्धान्तों की तुलना में इटली के विचारक विलफर्ड परेटो से करते है। परेटो ने यूरोपीयसमाज में व्याप्त असमानताओं का गहरा अध्ययन किया था। परेटो के शब्दों में – "समाज में किसी एक नागरिक के साथ निकृष्टतम किये बिना, कम से कम किसी एक नागरिक के साथ श्रेष्तम किया जा सकता है।" अम्बेडकर को भी मशीनों और स्पर्धात्मक उत्पादन व्यवस्था से कोई शिकायत न थी, लेकिन परेटो के समान वे चाहते थे कि न्याय–भावना के साथ सरकार लाभ का एक हिस्सा जरूरत मंदों तक पहुँचा कर असमानता की खाई को पाटने का काम कर सकती है। 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' के क्षेत्र में 'परेटो दक्षता तुल्यांक की चर्चा लगभग सभी आधुनिक अर्थशात्रियों ने किया है। (kashyap.op.wordpres)

अम्बेडकरवाद, मार्क्स का समाजवाद तथा बौद्ध धर्म– 'अम्बेडकरवाद' अम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय आम्बेडकरवाद के सिद्धान्त हैं। छुआछूत (अस्पृश्यता) को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हक की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की सचना और भारत देश की प्रगति यह प्रमुख उद्देश्य शामिल है। (जाधव नरेन्द्र–डा0 अम्बेडकर आर्थिक विचार एवं दर्शन him. wikipedia.org.– भीमराव अम्बेडकर विकिपीडिया)

अम्बेडकर ने मार्क्स की आलोचना करते हुए बुद्ध को अपनाया था अम्बेडकर के लिए बुद्ध इसलिए महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने जाति पर सवालिया निशान लगाते हुए समानता आधारित समाज का सपना देखा था। साम्यवाद के रूप में समानता आधारित समाज का सपना मार्क्स का भी था लेकिन मार्क्स समानता को जीवन के आर्थिक पक्ष से आगे बढ़कर नहीं देख पाये थे। हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर डॉ0 अम्बेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध धर्म सभा की स्थापना की तथा नागपुर में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया इनका प्रसिद्ध कथन था कि "मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा बौद्ध धर्म में।" (Sansarlochan.in - डॉ0 अम्बेडकर की जीवनी)

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नयनके असली नायक डॉ0 अम्बेडकर– बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि महिला अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण कई साल से चलन में है, सरकारों के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं। कई योजनाएं जैसे "बेटी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

बचाओ–बेटी पढ़ाओं'' सेल्फी विद डॉटर, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका शिक्षा योजना तथा महिला सुरक्षा एवं कल्याण योजना आदि–आदि। लेकिन भारत में महिला सशक्तिकरण के असली नायक बाबा साहब अम्बेडकर थे। 5 फरवरी 1951 को डॉ0 अम्बेडकर ने संसद में 'हिन्दू कोड बिल' पेश किया। यह बिल सभी वर्गों की महिलाओं के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक कदम था। महिलाओं को सामाजिक शोषण से आजाद कराना, पुरूषों के बराबर अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता रोजगार सृजन, प्रसूति अवकाश, महिला सुरक्षा, पैतृक सम्पत्ति में अधिकार आदि। लेकिन 'हिन्दू कोड बिल' संसद में पास कराना आसान नहीं था। संसद के अन्दर और बाहर विरोध के स्वर गुंजने लगे। इससे दुखी होकर बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ साल बाद 1955–56 हिन्दू कोड बिल के अधिकांश प्राविधानों को संसद ने पारित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भारतीय समाज में महिलाओं को जो अवसर प्राप्त हुए है वे 'संविधान शिल्पी' डॉ0 अम्बेडकर के प्रयासों का ही परिणाम हैं। (नीतू शाही–अम्बेडकर– महिला सशक्तिकरण केरियल नायक) ('हिन्दू नारी का उत्थान और पतन' भीमराव अम्बेडकर–2009 पृ0–24 ''क्रांति और प्रतिक्रांति– 2013 तृ0सं0 बी0आर0 अम्बेडकर खण्ड–7, पृ0– 335–336)

डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक– डॉ0 अम्बेडकर द्वारा किए गये शोध आज के समय के लिए भी उपर्युक्त हैं, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे– गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, पिछड़ापन, असमानता (व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय), विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा (रूपये) का अवमूल्यन आदि–आदि से सम्बन्धित गंभीर विमर्श डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष– डॉ0 अम्बेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता हो, गरीबी, बेरोजगारी और मंहगाई खत्म हो, लोगों का आर्थिक शोषण न हो तथा सामाजिक न्याय हों।

डॉ0 अम्बेडकर का योगदान किसी भी अर्थशास्त्री से कहीं ज्यादा है, डॉ0 अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों और शोधों का भारतीय समाज के संदर्भ में व्यावहारिक उपयोग किया। भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर डॉ0 अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के उद्देश्य को वास्तविक अर्थ में साकार किया है उनका यह अविस्मरणीय योगदान समाज और देश के प्रति असीम संवेदना और गहन वैचारिकी का परिणाम है। डॉ0 अम्बेडकर का माननता था कि ''आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी।'' प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासविद, आर0सी0 गुहा के अनुसार– डॉ0 वी0आर0 अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों का समना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की जरूरत है, तॉकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Reserve Bank of India-m.rbi.org.in BriesHistory- vol.1
2. भारतीय रिजर्व बैंक– संक्षिप्त इतिहास
   www.rbi.org.in 12 Jun, 2021
3. भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग की रिपोर्ट भारतीय संस्कृति 12 जून, 2021
4. Royal Institute of International Affairs (1929) the Hitton- yound and wilson Reports on East Af rica. pp. 267-71.
5. HiltonYoung Commission Report, pp, 41-8
   PP. 182-4, 201-3, 223-5, 228-31, 248.
6. R.G. Gregory (1971) India and East Africa : a History of reace relations within the British Empire, 1890-1939, Oxford, Clarendon Press.
7. B. Malinowski, (1929) Report of the Commission on closer union of the Dependencies in Eastern and Central Afric. Africa Journal of the International African Institute Vol.2, N0.3
8. E.A. Watter, (1963). The Cambridge History of the British Empire: South Africa. Rhodesia and the High Commission Territoies, cambridge Univerrity Press PP. 690-1
9. Report of the Royal Commission on Indian Currency and Finance. INDIAN CULTURE.

*****